प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अर्थव्यवस्था हर चीज की शुरुआत और अंत है, मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना आप सुधार नहीं कर सकते...
-डेविड कैमरन

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री

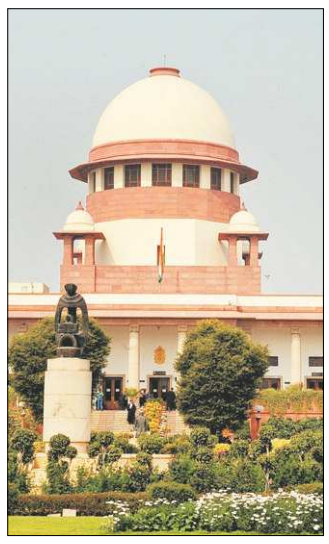

अयोध्या में गैरविवादित जमीन उसके मालिकों को लौटाने से संबंधित केंद्र सरकार की याचिका मंदिर निर्माण के मामले में उस पर पड़ते दबाव का ही सुबूत है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले इस दिशा में किसी सक्रियता पर इसीलिए सवाल उठे हैं।

अयोध्या पर पहलकदमी

अयोध्या में 67 एकड़ गैर विवादित भूमि उसके मालिकों को लौटाने से संबंधित केंद्र सरकार की सर्वोच्च न्यायालय में दी गई याचिका हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए बेशक बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले कुछ समय से सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना है। विहिप के अलावा संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मंदिर निर्माण के लिए सक्रियता की जरूरत बता चुके हैं, तो अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की धीमी गति पर खुद सरकार के कुछ मंत्री और भाजपा नेता तक अपनी बेचैनी जता चुके हैं। अलबत्ता अदालत में याचिका दायर करने का तात्कालिक कारण कुंभ में धर्म संसद द्वारा इस बारे में कोई घोषणा करने की बेचैनी से उपजा बताया जाता है। सरकार की पहल के बाद तो धर्म संसद ने अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू करने की तारीख भी तय कर दी है। दरअसल सरकार को यह लगने लगा है कि मंदिर निर्माण के क्षेत्र में उसकी पहलकदमी चुनाव से पहले लोगों को नई ऊर्जा से भर सकती है। पर अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले इस दिशा में सरकार की पहलकदमी को किस तरह से देखा जाए? जबकि खुद प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार अयोध्या मामले में अध्यादेश लाने के बजाय अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करेगी। सरकार का कहना है कि राम जन्मभूमि न्यास ने उसके हिस्से की गैर विवादित जमीन वापस मांगी है। पर न्यास ने ऐसी मांग कोई पहली बार नहीं की है। ऐसे ही जताया यह जा रहा है कि गैर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य में कोई परेशानी नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अपने एकाधिक निर्णयों में यह बता चुका है कि गैर विवादित जमीन का भविष्य भी विवादित जमीन पर आने वाले फैसले से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अंतिम फैसला आने से पहले कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि पूरी जमीन का अधिग्रहण करने का उद्देश्य खत्म हो चुका है। लिहाजा यह सवाल पूछा जा रहा है कि इतने वर्षों से यथास्थिति बहाल रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद केंद्र सरकार को अचानक, और वह भी चुनाव से ठीक पहले, उस आदेश को बदलने के लिए अदालत में याचिका डालने की जरूरत क्यों महसूस हुई है। अयोध्या को राजनीतिक नफे-नुकसान का खेल बना दिया गया है, इसलिए ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

कर सुधार की दिशा में

हमारी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का पहला चरण अभी चल रहा है और अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक दृष्टि से सभी के लिए मध्यम दर पर करों की नई व्यवस्था लागू होगी।

राजीव चंद्रशेखर, राज्यसभा सांसद

अभी हाल ही में हमने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन गरीबी और अभाव की समस्या अब भी हमारे देश के लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन को अपंग बना रही है। जैसा कि संसद में प्रवेश करने के बाद से लगभग हर बार बजट भाषण की बहस में भाग लेते हुए मैंने कहा है कि सिर्फ एक दशक तक आर्थिक विकास की दर उच्च दोहरे अंक में हो जाए, तो इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। विकास का मतलब सिर्फ उद्यमशीलता और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना भर नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीयों के लिए समान अवसर और समृद्धि के साथ भारत निर्माण के अंतिम लक्ष्य का एक साधन भी है।

गैर-कर अनुपालन से कर अनुपालन वाले समाज की ओर

समृद्ध भारत निर्माण का पहला कदम ऐसे भारत का निर्माण है, जहां हर भारतीय अपनी भूमिका निभाएं और अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह पालन करें। चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ *अर्थशास्त्र* में कहा है कि नागरिकों से कर संग्रह इस तरह से किया जाना चाहिए, जैसे मधुमक्खियां फूलों से मधु संग्रह करती हैं। कहने का मतलब यह कि नागरिकों से कर संग्रह उन्हें कष्ट पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए और उचित राशि ही कर के रूप में लेनी चाहिए। इन वर्षों में ईमानदार करदाताओं की त्रासदी यह थी कि उन्हें न केवल अपने हिस्से का कर अदा करना पड़ता था, बल्कि उन लोगों के हिस्से का कर अदा करने के लिए भी मजबूर किया जाता था, जो कर चुकाने से बचते थे।

पिछले सात दशक में ज्यादातर समय भारत एक निम्न कर-जीडीपी वाला राष्ट्र होने के कारण बदनाम रहा। इस समस्या से निपटने के लिए पहला वास्तविक सुधार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया गया, जब उनकी सरकार ने कर अनुपालन का विस्तार करने के लिए पहली कर सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। पिछले साल अक्तूबर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी किए गए आकलन वर्ष 2017-18 के इनकम टैक्स रिटर्न का आंकड़ा दिखाता है कि भारत में वास्तविक करदाताओं का दायरा कितना सीमित है। अनुमानित 8.6 लाख डॉक्टरों में से केवल 4.2 लाख या उससे कम डॉक्टर ही आयकर चुकाते हैं। तेरह लाख वकीलों में से मात्र 2.6 लाख ही कर चुकाते हैं। 2.8 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंटों में से केवल एक तिहाई या एक लाख ही कर चुकाते हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार ने करदाताओं के दायरे के विस्तार और कर अनुपालन को अपना लक्ष्य बनाया है। नोटबंदी सहित इसके प्रयासों और सुधारों ने प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात को दस साल के उच्चतम स्तर यानी लगभग छह प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। यह पिछले चार वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्न में 80 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2013-14 में 3.79 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 6.85 करोड़ हो गए। जैसे ही हम अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिककरण और टैक्स नेट के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी और निगरानी का उपयोग बढ़ाएंगे, यह आगे और बढ़ेगा। सात दशकों से जारी टैक्स चोरी की संस्कृति को खत्म करना न तो सरल है और न ही आसान। मुख्य रूप से इसकी आलोचना हुई है और इस पर आक्रमण किया गया है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।

आगे का रास्ता

कर विवाद संबंधी मुकदमे को कम करना- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मार्च, 2017 तक आयकर अपीलीय अधिकरण, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर से संबंधित लगभग 1,37,176 मामले विचाराधीन हैं और आयुक्त अपील, कस्टम, एक्साइज ऐंड सर्विस टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कुल 1.45 लाख अपील लंबित हैं। मार्च, 2017 के अंत तक मुकदमेबाजी (अपीलीय न्यायाधिकरण और ऊपर की अदालतों) में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के लगभग 7.58 लाख करोड़ रुपये के दावे अटके थे, जो जीडीपी के 4.7 फीसदी से ज्यादा है। प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता को कर मुकदमेबाजी को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें निवेश भावना और व्यापार करने में आसानी प्रत्यक्ष निहितार्थ हों।

प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना-सरकार को, विशेष रूप से उसके राजस्व विभागों को प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, डाटाबेस, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और एप्लिकेशन का उपयोग करना चाहिए, जो कर नेट विस्तार के अवसरों की पहचान करते हैं। ये सभी चीजें पहले से ही जीएसटीएन, आईटी रिटर्न, पैन और वित्तीय क्षेत्र के डाटा के साथ हैं। टैक्स नेट विस्तार के अगले चरण को संचालित करने के लिए वित्त मंत्रालय के भीतर एक अच्छी तरह से मानवयुक्त एनालिटिक्स डिवीजन या समूह की जरूरत है।

कम कर और उच्च अनुपालन का भविष्य

भारत का भविष्य कम कर दर और उच्च अनुपालन वाले राष्ट्र के रूप में होना चाहिए, जहां हर नागरिक सामान्य दर पर कर का भुगतान अनिवार्य रूप से करे। यह स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि जीएसटी और व्यक्तिगत कराधान के क्रमिक परिष्करण के साथ देखा गया है। यह न केवल चाणक्य की अर्थव्यवस्था की पुरानी दृष्टि को ध्यान रखना है, बल्कि सभी करदाताओं के लिए समान रास्ता बनाना भी है।

कॉरपोरेट और व्यक्तिगत करदाता दशकों से एक अनुचित और असमान व्यवस्था के शिकार हुए हैं, जहां ईमानदार लोगों को देश के विकास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कर चोरी करने वाले लोग बिना किसी दंड के पूरा आनंद लेते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का पहला चरण अभी चल रहा है और अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक दृष्टि से सभी के लिए मध्यम दर पर करों की नई व्यवस्था लागू होगी।

अंतर्ध्वनि

>> वर्जीनिया वुल्फ

कोई ताला नहीं, जो मस्तिष्क की आजादी को बंद कर सके

किताबें आत्मा का दर्पण होती हैं। अगर आप खुद से अपने बारे में सच नहीं कह सकते, तो दूसरों को भी सच नहीं बता सकते। एक औरत के रूप में मेरा कोई देश नहीं है। एक औरत के रूप में मुझे कोई देश चाहिए भी नहीं। एक औरत के रूप में मेरा देश पूरी दुनिया है। यदि आप चाहें, तो अपनी लाइब्रेरियों को बंद कर दें, पर कोई फाटक, कोई ताला नहीं है, जिससे कि आप मेरे मस्तिष्क की आजादी बंद कर सकें। मैं केवल यह कह सकती हूं कि अतीत सुंदर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भावनाओं का तत्काल एहसास नहीं कर पाता है। इसका विस्तार बाद में होता है। इसलिए हम वर्तमान भावनाओं का पूरी तरह से एहसास नहीं कर पाते, केवल अतीत का कर पाते हैं। अगर किसी ने अच्छी तरह से भोजन नहीं किया है, तो वह न तो ठीक से सोच सकता है और न सो सकता है। आप जैसे ही अपनी आंखों से सौंदर्य का आनंद लेते हैं, आपका दिमाग आपको बताता है कि सुंदरता खोखली है और सौंदर्य खत्म हो जाता है। मैं मोहक भ्रमों के बीच सोती हूं और उनके बोझ के साथ जागती हूं।

जो भी व्यक्ति योग्य है, वह सिर्फ वही पढ़ता है, जो उसे पसंद है, अपनी मनपसंद चीजों को वह अत्यधिक उत्साह के साथ पढ़ता है। जब मैं लिखती हूं, तो मेरे मन में कहीं वह विलक्षण और बहुत सुखद भावना सिर उठाती है, जो कि मेरा अपना दृष्टिकोण है। लिखते हुए साधारण शब्दों का चयन करें : असंबद्ध लेखन और वाक्-पटुता से बचें— फिर भी, यह सच है, कविता आनंददायक है; सबसे अच्छा गद्य वह है, जिसमें भरपूर काव्य विद्यमान है।

अगर आप अपनी फुरसत को खो रहे हैं, तो खबरदार! हो सकता है कि आप अपनी आत्मा को खो रहे हों।

-दिवंगत ब्रिटिश लेखिका

मंजिलें और भी हैं

>> एम नारायण मूर्ति

ट्रैफिक संभालने को बनाया राष्ट्र सेवा का नया जरिया

मैं 1959 में भारतीय सेना से जुड़ा था। जैसा कि आपको पता है कि सैनिकों का काम दुश्मनों को मारना ही नहीं होता, बल्कि अपनों को बचाना भी होता है। यह मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने शुरू से ही दूसरों को मारने के बजाय अपनों को बचाया ज्यादा है। मुझे देश के कई अहम सैन्य ऑपरेशनों में शामिल होने का मौका मिला। 1961 में गोवा को आजादी दिलाने में और 1962 में भारत-चीन युद्ध में मुझे अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। 1974 में जब मैं सेना से रिटायर हुआ, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण) से जुड़ गया और वहां 1974 से 1980 तक काम किया।

कहते हैं न कि हर आदमी को अपने जीवन की उपयोगिता साबित करने के लिए एक नहीं, बल्कि कई मौके मिलते हैं। ऐसा ही एक मौका मुझे 1990 में फिर मिला। तब मेरा सफर एअर इंडिया के साथ चल रहा था। वह मेरे लिए एक साथ हजारों भारतीयों की दुआएं कमाने का अवसर था, शायद इसलिए मैं उस वाकये को ताउम्र नहीं भुला सकता। गल्फ और पश्चिम एशियाई मुल्कों का कार्यभार संभाले हुए मैं जॉर्डन के अमन में तैनात था। यह वही वक्त था, जब नागरिक उड्डयन के इतिहास में पहली बार एक लाख से ज्यादा भारतीयों को संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास अंजाम दिया जाना था। और मैं इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा प्रभारी के रूप में जमीन पर काम कर रहा था। कुवैत की उस सफलता ने मुझे अद्भुत शांति प्रदान की।

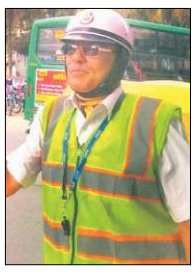

मैं कोशिश में हूं कि अपनी मुहिम को सड़कों के अलावा स्कूल-कॉलेजों तक ले जाऊं।

आज मेरी उम्र तिरासी साल से ज्यादा की हो चुकी है। भले ही मैं अब युद्ध के मैदान में लड़ने लायक नहीं बचा, लेकिन मेरे भीतर का फाइटर जिंदा है और मेरी लड़ाई भी जारी है। यह लड़ाई यातायात और इसके नियमों के प्रति लोगों के लापरवाह रवैये के खिलाफ है। मैं बंगलूरू की व्यस्त सड़कों के यातायात को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा हूं। ज्यादातर लोगों को यह एक छोटी-सी बात लग सकती है, लेकिन हमारी दिनचर्या की यही छोटी गलती किसी की बहुमूल्य जिंदगी तक लील सकती है।

मैं कोशिश में हूं कि अपनी मुहिम को सड़कों के साथ स्कूल-कॉलेजों तक ले जाऊं। मैं यातायात पुलिस के उस प्रयास से प्रभावित हूं, जिसमें वे बच्चों को यातायात नियम बताते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपने बड़ों को इन्हें मानने का आग्रह करेंगे। वास्तव में यह काफी अच्छा विचार है। यातायात की समस्या एक गंभीर मामला है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। सड़क सुरक्षा पर वर्तमान दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। मेरे हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों के अलावा समाज की और कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि यहां देश के युवा तैयार होते हैं।

अपने काम के लिए कर्नाटक सरकार ने मुझे 2011 में केंपागौड़ा पुरस्कार दिया था। लेकिन मैं किसी प्रकार के यश या सम्मान के लिए यह सब काम नहीं कर रहा। मैं बस अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा अर्थपूर्ण बनाना चाहता हूं।

मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर ऐसी जिम्मेदारियां निभाने और किसी भी तरह से समाज की सेवा करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए संसाधनों को समर्पित करना चाहिए।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

महिलाओं के श्रम की कीमत

ऑक्सफेम की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर साल महिलाएं 700 लाख करोड़ रुपये के अवैतनिक काम करती हैं। भारत में पितृसत्तात्मक सोच अब भी हावी है, जिसके तहत माना जाता है कि महिलाओं का जन्म सेवा कार्यों के लिए ही हुआ है।

ऋतु सारस्वत

हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में हर साल महिलाएं 700 लाख करोड़ रुपये के ऐसे काम करती हैं, जिनका उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। भारत में यह आंकड़ा छह लाख करोड़ रुपये का है। दुनिया भर में महिलाओं को लेकर एक ही सोच है कि उनका काम घर-परिवार की देखभाल करना है। इस सोच पर 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में अहम टिप्पणी देते हुए कहा था कि एक महिला बिना कोई भुगतान लिए घर की सारी देखभाल करती है। उसे होम मेकर (गृहिणी) और बिना आय वाली कहना सही नहीं है। महिला सिर्फ एक मां और पत्नी नहीं होती, वह अपने परिवार की वित्त मंत्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होती हैं। न्यायालय ने यह टिप्पणी पुडुचेरी बिजली बोर्ड की उस याचिका के संदर्भ में की थी, जिसमें बोर्ड को बिजली की चपेट में आकर मारी गई एक महिला को क्षतिपूर्ति के तौर पर चार लाख रुपये देने थे, जो कि बिजली बोर्ड को इसलिए स्वीकार नहीं थे, क्योंकि महिला एक गृहिणी थी और उसकी आय नहीं थी। न्यायालय ने बोर्ड की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा था कि हमें खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाई करना जैसे रोजाना के कामों को अलग नजरिये से देखने की जरूरत है।

एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक, 40 प्रतिशत ग्रामीण और 65 प्रतिशत शहरी महिलाएं पूरी तरह घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आंकड़ों के हिसाब से 60 से ज्यादा की आयु वाली एक चौथाई महिलाएं ऐसी हैं, जिनका सबसे ज्यादा समय घरेलू कार्य करने में ही बीतता है। पितृसत्तात्मक समाज में यह तथ्य गहरी पैठ बनाए हुए है कि स्त्री का जन्म सेवा कार्यों के लिए ही हुआ है। माउंटेन रिसर्च जर्नल के एक अध्ययन के दौरान उत्तराखंड की महिलाओं ने कहा कि वे कोई काम नहीं करतीं, पर विश्लेषण में पता चला कि परिवार के पुरुष औसतन नौ घंटे काम कर रहे थे, जबकि महिलाएं 16 घंटे। अगर उनके काम के लिए न्यूनतम भुगतान किया जाता, तो पुरुष को 128 रुपये और महिला को 228 रुपये मिलते।

कुछ देशों एवं संस्थानों ने घरेलू अवैतनिक कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग शुरू किया है। इन विधियों में से एक टाइम यूज सर्वे है। यानी जितना समय महिला घरेलू अवैतनिक कार्यों को देती है, यदि उतना ही समय वह वैतनिक कार्य के लिए देती, तो उसे कितना वेतन मिलता। कई देशों ने अवैतनिक कार्यों की गणना के लिए मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी का भी इस्तेमाल किया है। यानी जो कार्य अवैतनिक रूप से गृहिणियों द्वारा किए जा रहे हैं, यदि उन सेवाओं को बाजार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, तो कितनी लागत आएगी। संयुक्त राष्ट्र के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट से जुड़े डेबी बडलेंडर ने द स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑन केयर ऐंड नॉन केयर वर्क अक्रॉस सिक्स कंट्रीज नामक अपने अध्ययन में, अर्जेंटीना, भारत, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, निकारागुआ, दक्षिण अफ्रीका तथा तंजानिया का अध्ययन करने के लिए टाइम यूज सर्वे विधि का प्रयोग कर पाया कि अर्जेंटीना में जहां प्रतिदिन पुरुष 101 मिनट और महिला 293 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, वहीं भारत में पुरुष प्रतिदिन 36 मिनट और महिलाएं 354 मिनट अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं। दुनिया भर में कुल काम के घंटों में से महिलाएं दो तिहाई घंटे काम करती हैं, पर वह केवल 10 प्रतिशत आय ही अर्जित करती हैं और वे विश्व की मात्र एक प्रतिशत संपत्ति की मालकिन हैं।

एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना तब तक संभव नहीं, जब तक देश के हर नागरिक के आत्मसम्मान का संरक्षण न किया जाए। इस दृष्टि से घरेलू महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं।

खुली खिड़की

आर्थिक असमानता

हाल ही में जारी की गई ऑक्सफेम की रिपोर्ट में भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता पर चिंता व्यक्त की गई। नजर डालते हैं दुनिया के कुछ चुनिंदा विकसित देशों पर, क्योंकि वहां भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं।

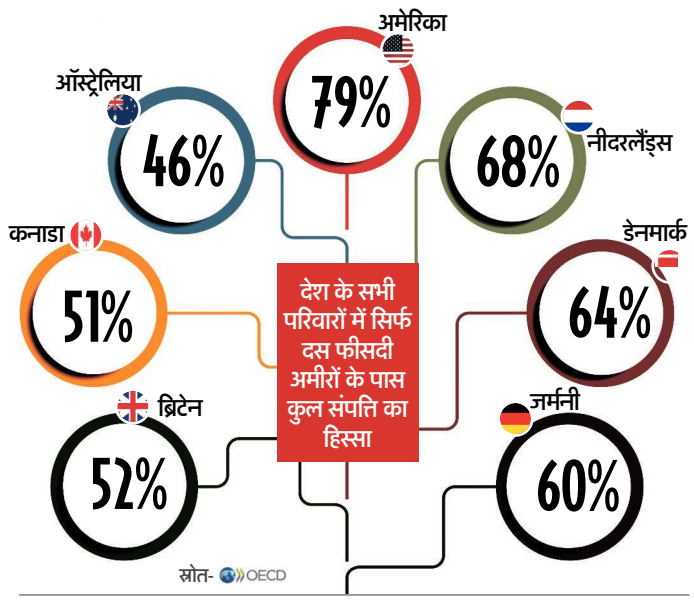

सत्संग

पहले चखकर देखता हूं

रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। बीस रुपये वेतन तय किया गया। पर पंद्रह दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और उनसे कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक शिकायत उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत यह थी कि यह अजीब पुजारी है, जो फल खुद चखकर भगवान को भोग लगाता है और फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्य नाराज थे और हैरान भी। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे, तब एक सदस्य ने पूछा, यह कहां तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? मैं पहले देख लेता हूं कि उस फूल से कुछ सुगंध आ भी रही है या नहीं? फिर दूसरी शिकायत रखी गई-सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो? रामकृष्ण ने उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी मां की याद है कि वह भी ऐसा ही करती थीं। जब भी वह कोई चीज बनाती थीं, तो चखकर देख लेती थीं, फिर मुझे खाने को देती थीं। मैं भी उसी तरह चखकर देखता हूं कि जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान के योग्य है भी या नहीं। यह सुन कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

मैम, किशोर और कागज का टुकड़ा

एक शिक्षिका की कहानी, जिसने छात्रों को दूसरों की अच्छाई ढूंढने के बारे में बताया।

अंजू मैम ने क्लास में आते ही सभी बच्चों को अपनी कॉपी से एक पन्ना निकालकर उसमें क्लास के सभी बच्चों के नाम लिखने को कहा। उनकी हिदायत यह भी थी कि दो नामों के बीच एक लाइन खाली छोड़ दी जाए। जब सबने नाम लिख लिए, तब मैम ने बीच की लाइन में हर बच्चे के बारे में एक अनोखी बात लिखने को कहा। मैम ने सबके पन्ने इकट्ठा किए और चली गईं। एक हफ्ते बाद मैम ने हर बच्चे को नया पन्ना दिया, जिस पर क्लास के बच्चों ने उसके बारे में जो कुछ लिखा था, वह था। यह देखकर सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। कई साल बाद अंजू मैम को एक दिन पता चला कि स्कूल का ही छात्र रह चुका किशोर, जो सेना में कैप्टन था, एक आतंकी हमले में शहीद हो गया। स्कूल के सभी शिक्षक किशोर को श्रद्धांजलि देने उसके घर पहुंचे। अंजू मैम को देख एक सैनिक उनके पास आकर पूछने लगा, क्या आप ही अंजू मैम हैं? जब मैम ने हां कहा, तो वह सैनिक बोला, किशोर आपको बहुत याद किया करता था। तभी किशोर के पिता आए और जेब से एक पुराना पर्स निकालने लगे। अंजू मैम को लगा कि शायद वह पर्स किशोर का होगा। किशोर के पिता उस पर्स में से कागज का एक पुराना टुकड़ा निकालने लगे। उसे देखकर लग रहा था, जैसे कि उसे कई बार पढ़ा गया हो। अंजू मैम को देखते ही समझ में आ गया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अंजू मैम को वह कागज देते हुए किशोर के पिता बोले, इस कागज ने किशोर की जिंदगी बदल दी थी। उसके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास आ गया था। वह जो भी करता था, उसमें सफल होता था। अक्सर जब किशोर से बात होती थी, तो वह कहता था, जब भी मैं अपने आप को कमजोर पाता हूं, तब यह कागज खोलकर जरूर पढ़ लेता हूं। फिर मुझे यह महसूस होता है कि मैं कितना अनमोल हूं।

आसपास के लोगों को यह बताना चाहिए कि उनमें क्या-क्या खूबियां हैं।